

भारतीय संविधान में सभी की प्रगति की भावना पर जोर: लोक सभा अध्यक्ष

एजेंसी नई दिल्ली/ताशकंद। लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारतीय संविधान के समावेशी और कल्याणकारी स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान मानने, उन्हें समान अवसर प्रदान करने तथा वंचित और पिछड़े वर्गों के लोगों को प्रगति की मुख्य धारा से जोड़ने की भावना प्रधान है। ताशकंद (उज्बेकिस्तान) में अंतर-संसदीय

संघ (आईपीयू) की ऐतिहासिक 150वीं सभा में सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय प्रयास विषय पर मुख्य भाषण देते हुए बिरला ने कहा कि भारत की संसद ने हाल के वर्षों में ऐसे अनेक विधेयक पारित किए हैं, जो सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा तथा सभी वर्गों के समावेशन को बढ़ावा देते हैं। समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए संसद की प्रतिबद्धता का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम - 2016', उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' और 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023' जैसे कानून समाज के सभी वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। इस संदर्भ में उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए संसद से पारित नए श्रम कानूनों और संहिताओं का उल्लेख भी किया। उन्होंने आईपीयू असेंबली में



भाग ले रहे प्रतिभागियों को रामनवमी की शुभकामनाएं भी दीं। बिरला ने कहा कि भारतीय दंड संहिता' को 'भारतीय न्याय संहिता' से प्रतिस्थापित कर भारत ने न्याय की प्राथमिकता को स्थापित किया है। विकास और सामाजिक न्याय के लक्ष्यों को प्राप्त करने में संसदीय समितियों के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बिरला ने कहा कि विभिन्न संसदीय समितियां, जिन्हें हम मिनी संसद भी कहते हैं, संसद व सरकार

के प्रयासों के पूरक के रूप में कार्य करती हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता संबंधी समिति, महिला अधिकारिता संबंधी समिति, श्रम और कौशल विकास संबंधी समिति तथा अन्य विविध समितियां कल्याणकारी कार्यक्रमों की निगरानी करती हैं, जिससे योजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावी तथा जवाबदेह ढंग से हो।

बिरला ने इस बात पर जोर दिया

कि भारत सरकार मानव विकास के प्रमुख संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन के साथ काम कर रही है। इस संबंध में उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री - जन आरोग्य योजना (पीएम-जोएवाई) के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़ी भारत की 40 फीसदी आबादी को निशुल्क स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी जा रही

है। बिरला ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में 105 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि के साथ भारत पिछले एक दशक में विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है तथा विकसित भारत-2047 के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है।बिरला ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

वक्फ संशोधन से जदयू में कोई नाराजगी नहीं : संजय झा

एजेंसी पटना। जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा ने कहा कि वक्फ संशोधन को लेकर पार्टी में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि यह कोई पहली बार संशोधन नहीं हुआ है, इसके पहले भी संशोधन हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि बिहार के पसमांदा मुसलमानों के बीच अब बेहतर काम हो जाएगा। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जदयू नेता ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक लाने का उद्देश्य गरीब मुसलमानों को इसकी सही सुविधा देना है। जेपीसी बनी तो हमारी पार्टी के लोग भी थे। मुस्लिम समाज के लोग भी नीतीश कुमार से मिले। उन्होंने स्पष्ट कहा कि गरीब मुसलमानों को अब इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। पूरी पारदर्शिता आएगी और सही जगह पैसा लगेगा। इस विधेयक के खिलाफ कई पार्टियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह किसी का अधिकार है। अदालत इसे लेकर तय करे। लेकिन उसका उद्देश्य व्यापक सुधार है। पसमांदा और महिला समाज को ज्यादा लाभ होगा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि बिहार में सबसे अधिक पसमांदा समाज के मुसलमान हैं, लेकिन क्या वक्फ से उनके बीच कोई काम हुआ है? अस्पताल बना है, स्कूल खुला है? उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इसे लेकर जदयू में कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि 2005 के पहले पंचायत चुनाव में आरक्षण था? जब नीतीश कुमार सत्ता में आए, तब आरक्षण मिला। पसमांदा समाज के लोग आज मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य बने हुए हैं, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही देन हैं।



यूपी में वन अपराधों पर अंकुश लगाने और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए चलेगा अभियान

एजेंसी लखनऊ। उत्तर प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने की दिशा में अग्रसर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में 8 अप्रैल से 8 मई तक वन और वन्य जीव सुरक्षा माह का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत प्रभागों में वन अपराधों पर अंकुश लगाने और वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जाएगा। इसमें वन बल और पुलिस के साथ ही नेपाल सीमा पर एसएसबी आदि सुरक्षा बलों का भी सहयोग लिया जाएगा। साथ ही नागरिकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया जाएगा। प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि यह अभियान 8 अप्रैल से 8 मई तक प्रतिदिन चलेगा। प्रतिदिन तीन शिफ्ट में इस अभियान को चलाया जाएगा। पहली शिफ्ट सुबह छह से दोपहर दो तक, दूसरी दोपहर दो से रात्रि 10 और तीसरी शिफ्ट रात्रि 10 से सुबह छह बजे तक चलेगी। इसके लिए प्रभागों में टीम का गठन किया जा रहा है। यह टीम वन भूमि पर होने वाले अतिक्रमण को भी हटाएगी। जौनल/मंडलीय वन संरक्षक अभियान के नोडल अधिकारी होंगे। वे प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक व विभागाध्यक्ष कार्यालय में स्थापित कमांड सेंटर को भेजेंगे। साथ ही नोडल अधिकारी की देखरेख में आमजन को हरीतिमा बढ़ाने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं पर नजर रखने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। अभियान के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं को भी न्यूनतम करने के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। अग्नि नियंत्रण सेल मुख्यालय के नोडल अधिकारी पीपी सिंह ने बताया कि गर्मियों में वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं न हों, सुरक्षा माह में इसके लिए भी आमजन को जागरूक किया जाएगा। आमजन को बताया जाएगा कि जंगलों या वन क्षेत्र में आग की छोटी से छोटी घटनाओं की जानकारी प्रभागीय वनाधिकारी या अग्नि नियंत्रण सेल को दें, जिससे घटनाओं को समय रहते रोका जा सके। आमजन को हेलपलाइन नंबर की भी जानकारी दी जाएगी।



प्रयागराज की दरगाह पर भगवा झंडा लहराने का मामला :पुलिस सख्त, जांच जारी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां सिकंदरा क्षेत्र में स्थित एक दरगाह पर भगवा झंडा लहराया गया और धार्मिक नारेबाजी की गई। घटना रविवार की है जब 20 से अधिक युवक बाइक रैली के जरिए सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह तक पहुंचे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, रैली के दौरान तीन युवक दरगाह के मुख्य द्वार पर चढ़ गए और भगवा झंडा लहराते हुए नारे लगाने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन हस्तकत में आया। डीसीपी गंगापुर, कुलदीप सिंह गुनावत ने स्पष्ट किया, +6 अप्रैल को थाना बहरिया क्षेत्र के अंतर्गत स्थित इस दरगाह पर, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के श्रद्धालु आते हैं, कुछ युवकों ने धार्मिक झंडा लहराकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उन्हें मौके पर मौजूद पुलिस ने तत्काल रोका और वहां से हटाया। पुलिस ने बताया है कि इस मामले में आराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, जिस स्तर पर पुलिस कमियों से लापरवाही हुई, वहां विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह एक साझा आस्था का केंद्र मानी जाती है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोग मनोनी मानने आते हैं। ऐसे में यह घटना धार्मिक सौहार्द को चोट पहुंचाने वाली कही जा रही है।

सनातन धर्म को नाथ संप्रदाय ने शक्ति देने का काम किया: अमित शाह

108 कुण्डीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ में शामिल हुए केन्द्रीय मंत्री शाह

एजेंसी कोटपुतली-बहरोड़ा। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि महाप्रभु आदिनाथ से लेकर उनके अनुयायियों तक, इस संप्रदाय ने सनातन धर्म को स्थायित्व और शक्ति दी है। नाथ परंपरा में धृनि को आत्मज्ञान प्राप्ति का साधन माना गया है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश जैसे पंचतत्वों को संतुलित कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। केन्द्रीय गृह एवं



सहकारिता मंत्री अमित शाह राजस्थान के कोटपुतली में आयोजित 108 कुण्डीय रुद्र

संबोधित किया। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। केन्द्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबा बस्तीनाथ ने समाज के सभी वर्गों को जोड़कर एक वर्ष तक यह आयोजन सतत रूप से संचालित किया, जो एक बड़ा और प्रेरणादायक कार्य है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन की शुरुआत पिछले वर्ष रामनवमी पर हुई।

सनातन संस्कृति, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत केंद्र है चित्रकूट : मुख्यमंत्री डॉ यादव

सनातन संस्कृति, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत केंद्र है चित्रकूट : मुख्यमंत्री डॉ यादव

एजेंसी भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि चित्रकूट केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, हमारी सनातन संस्कृति, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का जीवंत केंद्र है। यह परमधाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की तपोस्थली है, जहां भगवान श्रीराम, माता जानकी और भैया लखन के साथ सदा सर्वदा निवास करते हैं। रामनवमी के दिन में तपोभूमि चित्रकूट में आकर धन्य हो गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव भगवान श्रीराम की तपोभूमि चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर भरत घाट पर



संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यहां भरत घाट पर दीपदान किया और मां मंदाकिनी की पूजा-अर्चना भी की।

इस अवसर पर चित्रकूट में भरत घाट पर 11 लाख दीप जलाए गए, जिससे पूरा घाट जगमगा उठा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि आज का दिन सौभाग्यशाली है। आज पवित्र नौवीं तिथि है और कामतानाथ जी की नगरी चित्रकूट अपना गौरव दिवस मना रही है।

चित्रकूट के घाटों पर असंख्य दीपदान की अलौकिक छटा दिख रही है। भरत घाट, कामदगिरि पर्वत, कामतानाथ स्वामी मंदिर के साथ चित्रकूट के सभी मंदिरों और घर-घर एवं गली, मोल्लों, रास्तों में दीपमालाओं की अनुपम छटा देखते

ही बन रही है। उन्होंने नगर वासियों को रामनवमी एवं चित्रकूट गौरव दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चित्रकूट में सद्गुरु सेवा ट्रस्ट, दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा पीड़ित मानवता की सेवा के लिए नाना जी के संकल्पों को पूरा किए जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 19 धार्मिक स्थलों में एक अप्रैल से शराबबंदी लागू कर दी गई है, जिससे हमारे देव स्थानों में विकृतियां न पनपें।

प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार जनकल्याणकारी और विकास कार्य कर रही है सरकार : शिवराज

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने गैरतगंज में नवीन आईटीआई भवन और रमपुरा में 33/11 केवी उपकेन्द्र का किया लोकार्पण

एजेंसी रायसेन। केन्द्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। यह दृढ़ संकल्प है कि जनता के जीवन में कोई तकलीफ न हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लगातार जनकल्याणकारी और विकास कार्य कर रही है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। साल में एक लाख से अधिक लखपति दीदी बनेंगीं। हर महिला को स्व-सहायता समूह से जोड़ा जाए। केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान रायसेन जिले के गैरतगंज में आयोजित

शासकीय आईटीआई भवन का लोकार्पण सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कन्यापूजन और दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि गाँवों को गरीबी मुक्त बनाना है। विकसित भारत में कोई गरीब नहीं होगा। नौ गांव आदर्श ग्राम बनाए जाएंगे। गांव के लोग तय करें कि किस तरह से गरीबी दूर की जा सकती है। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों का पक्के मकान का सपना साकार हो रहा है। वर्षों से कच्चे



मकान और झोपड़ी में रह रहे गरीबों के सिर पर अब पक्की छत है। कोई भी पात्र परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ से छूटेगा नहीं, सर्वे

करके सभी पात्र हितग्राहियों के पक्के मकान बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले सात महीने में ही सांची विधानसभा क्षेत्र में 7385

हितग्राहियों के पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के सर्वे से छूटे नहीं। जल जीवन मिशन का उल्लेख करते हुए केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचे, इसके लिए जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर में टोंटी से जल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मंच से ही पीएचई तथा जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नल जल योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए जिससे कि प्रत्येक घर में नल से जल पहुंचे। कार्यक्रम में

सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी ने कहा कि आज केन्द्रीय कृषि मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान द्वारा यहां शासकीय आईटीआई के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया है। इसमें नवीन व्यवसाय के लिए छह ट्रेड का मुख्य भवन, 60 सीटर बालक छात्रावास, 60 सीटर बालिका छात्रावास, एक नग एफ टाइप आवास गृह, दो नग एच टाइप और चार नग आई टाइप आवास गृहों का निर्माण किया गया है। यह जिले की सबसे बड़ी आईटीआई है। इस आईटीआई से न सिर्फ गैरतगंज बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी लाभ मिलेगा।

राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद तुगलक रोड थाने में हाईकोर्ट जज के घर जले नोटों की रिपोर्ट दर्ज नहीं

एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास पर 14 मार्च, 2025 को आग लगने की घटना के बाद भी तुगलक रोड थाना पुलिस द्वारा जले हुए नोटों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। जबकि इस मामले में राष्ट्रपति सचिवालय से भी कार्रवाई के निर्देश जारी हो चुके हैं। घटना के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने प्रारंभिक जांच कर 22 मार्च, 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचित किया था कि जज वर्मा के घर में नोट रखे हुए थे जो आग में जल गए। पुलिस कमिश्नर द्वारा उन्हें इस संबंध में वीडियो भी भेजा

गया था। हालांकि, जज वर्मा ने स्पष्ट रूप से इन नोटों को अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का होने से इनकार किया था और इसे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की साजिश बताया था। 25 मार्च तक कोई रिपोर्ट दर्ज न होने पर, राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर के अधिकतम पूनम चंद भंडारी ने तुगलक रोड थाने में एक रिपोर्ट भेजी। उन्होंने तर्क दिया कि जब जज वर्मा ने जले हुए नोटों को अपना नहीं बताया है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जानी चाहिए थी। भंडारी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी प्रेस नोट और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट लिखकर अनुरोध किया।



पहुंचा है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। जानकारी के अनुसार, बीकानेर से बिलासपुर जा रही ट्रेन संख्या 20846 बीकानेर-

बिलासपुर एक्सप्रेस शाम करीब चार बजकर 35 मिनट पर उज्जैन से

आग लग गई। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन को लोको पायलट ने जंगल में ही पावर कोच से अलग कर दिया। जलते पावर कार को लेकर इंजन थाना स्टेशन पहुंचा। यहां पहले से ही रेलवे कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दे दी थी। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पकचाया। सूचना मिलते ही रेलवे का तक्रनीकी अमला भी मौके पर पहुंच गया और ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। उसके बाद उसी इंजन को फिर से बिलासपुर जा रही ट्रेन संख्या

पति से झगड़े के बाद महिला ने की खुदकुशी

एजेंसी
नई दिल्ली। कल्याणपुरी इलाके में एक महिला ने पति से झगड़े के बाद फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतका की पहचान 35 वर्षीय अनुराधा के रूप में हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शवगृह में भेज दिया है। पुलिस को फिलहाल मृतका के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मृतका के परिजनों से पूछताछ कर आत्महत्या के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस के मुताबिक अनुराधा परिवार के साथ ईस्ट विनोद नगर इलाके में रहती थी। परिवार में पति गौरव के अलावा अन्य सदस्य हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार को अनुराधा और गौरव के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े के बाद शाम के वक्त अनुराधा ने कमरे में पंखे के सहारे चुन्नी से फांसी लगाकर जान दे दी। घटना का पता चलते ही परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चुन्नी काटकर शव नीचे उतारा गया। क्राइम टीम को घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने के लिए बुलाया गया। अभी तक की जांच में पता चला है कि महिला ने पति से झगड़े के बाद यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है।

चोरी के मामले में तीन आरोपित गिरफ्तार

नई दिल्ली। दक्षिण पश्चिम जिले के कपासहेड़ा थाना पुलिस ने चोरी के मामले में जांच के बाद तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की पहचान प्रमोद कुमार, गौरव और करण रावल के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चोरी के तीन मोबाइल बरामद किए हैं। दक्षिण पश्चिम जिले के डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि सात मार्च को कुपाल शर्मा ने आई फोन सहित कुल 93 मोबाइल की चोरी की शिकायत दी। इंस्पेक्टर विक्रम दहिया ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने चोरी किए गए मोबाइल के दस्तावेज बरामद किए और चोरी हुए मोबाइल फोन के सभी आईएमईआई नंबरों को आगे ट्रैकिंग के लिए निगरानी में रखा गया। 93 मोबाइल फोन में से तीन मोबाइल फोन फरीदाबाद में चालू पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने प्रमोद कुमार, गौरव और करण को दबोचा।

रुपयों के विवाद में सब्जी वाले की पीट पीटकर हत्या

नई दिल्ली। दक्षिण पूर्वी जिले के कालिंदी कुंज इलाके में रुपयों के विवाद में एक शख्स ने सब्जी वाले को पीट पीटकर अधमरा कर दिया। घायल को परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ व सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद गैर इरादतन हत्याका मामला दर्ज किया। फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है। दक्षिण पूर्वी जिले के डीसीपी रवि कुमार ने बताया मृतक की पहचान मुन्ना महतो के रूप में हुई है। वह परिवार के साथ मकान नंबर ए2/1133, जलेबी चौक, जेजे कॉलोनी रहता था। मुन्ना घर के पास ही सब्जी की दुकान लगाता था। डीसीपी ने बताया कि शनिवार की सुबह करीब 9.13 बजे दुकान पर एक डाकड़ सब्जी खरीदने के लिए आया था। सब्जी खरीदने के दौरान उसका पैसों को लेकर मुन्ना से झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान आरोपित ने मुन्ना की पिटाई कर दी। जिससे वह बेहोश हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

पुलिस माल खाने में लगी आग, 345 गाड़ियां जली

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ती गर्मी के बीच आग लगने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार तड़के वजीराबाद के पास दिल्ली पुलिस के पिट (माल खाना) में आग लग गई। घटना में काफी संख्या में गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। दमकल विभाग को 4:30 बजे के आसपास आग लगने की सूचना मिली थी। मौके पर अलग-अलग फायर स्टेशन से आग बुझाने वाली आठ गाड़ियां पहुंची और डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि आग बुझाने के दमकलकर्मियों की टीम ने लगातार कुलिंग का काम किया। जिससे कि दोबारा आग ना भड़क सके। स्टेशन ऑफिसर मनोज त्यागी की टीम ने आग को सुबह साढ़े छह बजे के आसपास बुझाया। पूरी तरह कुलिंग करने के बाद दमकल की गाड़ियां मौके से लौटी। वहीं इस आग की चपेट में आकर 345 गाड़ियां जल गईं। जिनमें से 260 स्कूटी और बाइक बाकी 85 कार शामिल हैं। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत या घायल नहीं हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार यह माल खाना दक्षिण जिला पुलिस का है।



वक्फ संशोधन विधेयक को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, कानून का नाम भी बदला

एजेंसी
नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई। इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी और डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है। विपक्षी दलों और कई मुस्लिम संगठनों के विरोध के बावजूद लोकसभा ने 3 अप्रैल को तड़के और राज्यसभा ने 4 अप्रैल को तड़के होने के साथ ही प्रदान की। लोकसभा में इसके समर्थन में 288 और विरोध में 232 वोट पड़े थे जबकि ऊपरी सदन में इसके ध्वंश में 128 और विरोध में 95 वोट पड़े। नए वक्फ कानून का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग, पक्षपात और अतिक्रमण को रोकना है। सरकार का कहना है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के सही प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करना है। राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून पूरे देश में लागू हो गया है, जिससे वक्फ संपत्तियों की सुस्था और उचित उपयोग को लेकर नई दिशा मिलेगी।



इस कानून के लागू होने से वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।बता दें कि इस बिल में वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं को शामिल करना, वक्फ संपत्तियों का डिजिटलीकरण, कलेक्टर को सर्वेक्षण का अधिकार, और ट्रिब्यूनल

शहरी परिवहन नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के प्रबन्धक अनुज दयाल ने बताया कि फेज-चौथा का लाजपत नगर - साकेत जी ब्लॉक मेट्रो

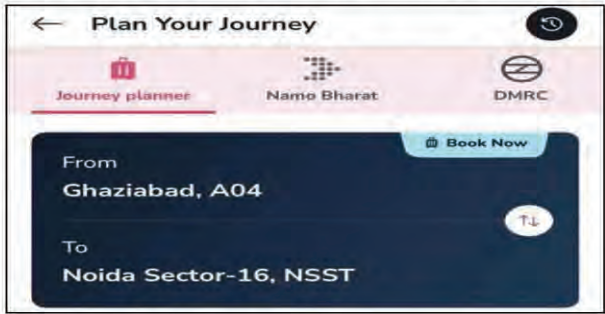
अब नमो भारत ऐप के जर्नी प्लानर फीचर से एंड टू एंड ट्रिप प्लानिंग, सिंगल विंडो पेमेंट की सुविधा

जर्नी प्लानर फीचर एकीकृत एवं सुविधाजनक यात्रा की ओर एक सशक्त कदम

एजेंसी गाजियाबाद। नमो भारत यात्रियों की यात्रा को और सुविधाजनक बनाने के लिए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ऐप में एक आकर्षक फीचर, जर्नी प्लानर की शुरुआत की है। इस फीचर के साथ यात्री एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नमो भारत और मेट्रो नेटवर्क में अपनी पूरी यात्रा की योजना बना सकते हैं, सबसे आसान एवं सुविधाजनक यात्रा मार्ग के विकल्प चुन सकते हैं और एक ही जगह सहज भुगतान के साथ बुकिंग पूरी कर सकते हैं। यह यात्रियों के लिए एकीकृत एवं सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने की ओर बढ़ाया गया एक सशक्त कदम है। एनसीआरटीसी के प्रवक्ता प्रवीण वत्स ने बताया कि इस फीचर के साथ, यात्री नमो भारत एप पर ही

अपनी एंड टू एंड यात्रा की योजना बना सकते हैं। यह फीचर एक स्टेशन से दूसरे के बीच के यात्रा के

दोनों के टिकट एक साथ बुक करने की सुविधा। इससे यात्रियों का दो अलग- अलग एप पर जाकर दोनों



लिए स्मार्ट रूट का सुझाव देता है। यात्री इससे सबसे तेज और सबसे कूल रूट की जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ अनुमानित यात्रा समय और सुझाए गए इंटरचेंज भी देख सकते हैं। इसमें नमो भारत, मेट्रो एवं फ्रस्ट एंड लास्ट माइल की यात्राएँ शामिल हैं। एक और चीज जो इस प्रीचर को खास बनाती है, वो है एक ही प्लेटफॉर्म पर नमो भारत और मेट्रो

माध्यमों के लिए अलग-अलग टिकट बुक करने की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे नमो भारत एप पर ही पूरी यात्रा का अनुमानित किराया देखकर, यूपीआई, डेबिट/क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग द्वारा एकल और सुविधित भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इसका प्रयोग करने के लिए यात्रियों को नमो भारत एप के जर्नी प्लानर सेक्शन में

आर्य समाज के 150 साल पूरे : विजेंद्र गुप्ता और प्रवेश वर्मा ने बताया मानवता की सेवा का बेहतरीन उदाहरण

एजेंसी नई दिल्ली।आर्य समाज के मानव सेवा के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा शामिल हुए।इस समेलन को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने आर्य समाज की समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण में भूमिका की सराहना की। कार्यक्रम में आर्य समाज के योगदान को याद किया गया और इसके मूल्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा, «आर्य समाज ने हमेशा पाखंड और आडंबरों का विरोध किया है। इसने समाज को नई दिशा दी और राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। आर्य समाज के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए।' उन्होंने आर्य समाज के कार्यों को मानवता की सेवा का बेहतरीन

उदाहरण बताया। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने संबोधन में कहा, मेरा परिवार शुरू से ही आर्य समाज से जुड़ा रहा है। मेरे पिता हर



हवन करते थे। मुझे अपने पिता से ही आर्य समाज के संस्कार मिले हैं।' उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से समर्थन का वादा करते हुए कहा, 'अक्टूबर में होने वाले आर्य समाज सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। दिल्ली सरकार इस आयोजन के साथ पूरी तरह खड़ी है। प्रवेश वर्मा ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा,

«पहले की सरकारों ने ऐसे आयोजनों के लिए कोई सहयता नहीं दी। वे सिर्फ मस्जिदों के मौलवियों को वेतन देने में लगी रहती थी। हमारी सरकार

ने इस प्रथा को बंद कर दिया है। अब हम समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। यह आयोजन आर्य समाज के 150 साल के सफर को सेलिब्रेट करने के लिए था, जिसमें संगठन के सामाजिक सुधार, शिक्षा और मानव सेवा के कार्यों को याद किया गया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।

जमीअत उलमा-ए-हिंद ने वक्फ संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

एजेंसी नई दिल्ली। संसद के दोनों सदनों से पारित वक्फ संशोधन कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जमीअत उलमा-ए-हिंद ने इस कानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि यह कानून भारतीय संविधान पर सीधा हमला है। भारत का संविधान 1861 में तैयार किया गया था, जबकि मुस्लिमों की नियुक्ति को नुकसान नहीं होगा, बल्कि करोड़ों गरीब मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। राज्य वक्फ बोर्डों में कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने (संशोधन) विधेयक, 2024 को लोकसभा में पेश करने के बाद विपक्ष की आपत्ति के कारण उसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया था।

स्वतंत्रता छीनने की साजिश है, जो पूरी तरह संविधान के खिलाफ है। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर यह बिल कानून बन गया तो हम इसे देश की सर्वोच्च अदालत में चुनौती देंगे। इसलिए राष्ट्रपति की मुहर लगते ही जमीअत ने आज इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायित्व कर दी है। उन्होंने कहा कि जमीअत की राज्य इकाइयां भी इस कानून के खिलाफ संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट में याचिकाएं दायित्व करेंगी। उन्हें

न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि इस असंवैधानिक कानून पर भी हमें न्याय मिलेगा। तथ्यांकित सेक्युलर दलों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस कानून को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए, लेकिन खुद को सेक्युलर कहने वाली पार्टियों ने न सिर्फ मुसलमानों के हितों का सीदा किया, बल्कि संविधान को भी अपने पैरों तले कुचल डाला और अपने असली चेहरे को पूरे देश के सामने उजागर कर दिया। मौलाना ने उन सभी सेक्युलर सांसदों का शुक्रिया अदा किया, जो देर रात तक संसद में डटे

रहे और इस कानून के संभावित दुष्परिणामों को अपने भाषणों के जरिए उजागर किया। साथ ही उन्होंने उन न्यायप्रीय नागरिकों का भी आभार प्रकट किया, जो संसद के बाहर इस कानून के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि आज भी देश में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनमें अन्याय के खिलाफ बोलने का साहस और जज्बा है। यह कानून केवल धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं है, बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और उसके मार्गदर्शक सिद्धांतों के विरुद्ध है।

एनडीएमसी के शिविर में मिलीं 65 जन शिकायतें

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने क्षेत्रीय लोगों और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के लिए एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शिकायत निवारण सुविधा शिविर का आयोजन किया। इसमें लोगों से जुड़ी जानकारीयें, सुविधा, सूचना और शिकायतों का समाधान एक ही जगह पर उपलब्ध किया गया। एनडीएमसी के अधिकारियों को शिविर में जनता से 65 शिकायतें प्राप्त हुईं। नई दिल्ली क्षेत्र के निवासियों की अधिकांश शिकायतें कार्मिक, सविल इंजीनियरिंग, बागवानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रवर्तन, वाणिज्यिक, कर और संपदा विभागों से संबंधित थीं। एनडीएमसी नागरिक सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सैकड़ों स्थानीय निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं ने सुविधा शिविर का दौरा किया। सभी सार्वजनिक शिकायतों पर जनता द्वारा एनडीएमसी के विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारियों के साथ शीघ्र समाधान के लिए चर्चा की गई। शिकायतों के निवारण के लिए एनडीएमसी के 30 विभागों के सी से अधिक अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर में मौजूद थे। विभिन्न विभागों के हेल्प डेस्क की देखरेख विभागाध्यक्षों द्वारा की गई। इन सुविधा शिविरों के आयोजन के अलावा पालिका परिषद ने एनडीएमसी क्षेत्र के निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए संपर्क रहित शिकायत निवारण तंत्र के रूप में एक जन सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया है।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की देशव्यापी सघर्ष की घोषणा

एजेंसी नई दिल्ली। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की समस्याओं के लिए देशव्यापी सघर्ष की घोषणा की है। यह आंदोलन सालभर चलेगा। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पाण्डेय ने यह जानकारी प्रकरार की। उन्होंने कहा कि साल के आखिर में नई दिल्ली में संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। संवाददाता सम्मेलन में प्रमुख रूप से उतर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल सहित अन्य 14 राज्यों के पदाधिकारी मौजूद रहे। शिक्षक नेता पाण्डेय ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में संवाददाता सम्मेलन पूरी कार्ययोजना का विवरण साझा किया। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र और राज्य सरकारों ने समस्याओं का समाधान नहीं किया तो राजनीतिक पार्टी से चुनाव भी लड़ एकजुट होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। पाण्डेय ने कहा कि इस साल देश के सभी राज्यों और जपसद मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। इस दौरान प्रशासन के माध्यम से शिक्षकों की समस्याओं पर केंद्रित ज्ञान के केंद्र और राम सरकारों को भेजे जाएंगे। कुछ

समय से संगठन के पदाधिकारियों के विवाद पर सवाल पूछे जाने पर संघ के उपाध्यक्ष रामअतार पाण्डेय ने बताया कि कतिपय लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि वह लोग ही असल पदाधिकारी हैं। ऐसा करने वालों में पूर्व महासचिव कमलकान्त त्रिपाठी और वासुराज गुरीकर प्रमुख हैं। ओडिशा निवासी त्रिपाठी सेवानिवृत्त हैं। वह बीजू जनता दल के सक्रिय सदस्य हैं। साथ ही बीजद के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। ऐसा करना संघ का नियमावली का उल्लंघन है। संघ के दूसरे नेता घनश्याम प्रसाद यादव ने आरोप लगाया कि त्रिपाठी लगातार संगठन को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। उनके बहकावे में आकर सेवानिवृत्त वासुराज गुरीकर उनका साथ दे रहे हैं। गुरीकर तो एक राजनीतिक पार्टी से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनका साथ पूर्व पदाधिकारी रंमाराज भी दे रहे हैं। रंमाराज उनकी समानांतर खड़ी हैं उनकी कार्यकारिणी के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट में गुहार लगाई गई है। हाई कोर्ट ने सत्यापन के लिए तीन सदस्यीय पूर्व न्यायाधीशों की कमेट्री गठित की।

कमेटी की आख्या पर हाई कोर्ट ने कार्यकारिणी को अवैध घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील पाण्डेय ने साफ किया कि पंजीकृत नियमावली के अनुसार रामपाल सिंह अध्यक्ष थे। 22 सितम्बर, 2023 को उनका देहांत हो गया। उनके कार्यकाल में मैं (सुशील कुमार पाण्डेय) उपाध्यक्ष (प्रथम) था। नियमावली के अनुसार अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष (प्रथम) को समस्त कार्य एवं संघ की कार्यवाही संचालित करने का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए यह दाहिय स्वतः मुझे मिल गया। इस दौरान पूर्व महासचिव कमलकान्त त्रिपाठी ने नियमावली की अवहेलना करते हुए उनके खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। राज्य इकाइयों को प्रलोभन देकर बगलालाया गया। इससे चितित संघ महासभा ने अक्टूबर में बैठक बुलाकर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक में महासभा के निर्वाचन कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर पंयवक्ता और निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए।

दयाल ने बताया कि अधिकांश 4, 6 या 8 कोच वाली ट्रेनों का उपयोग करने वाली मेट्रो लाइनों के निपटीत, इस अभिनव 3 कोच प्रणाली को विशेष रूप से कम दूरी की यात्रा के लिए विकसित किया गया है। छोटी ट्रेन

संरचना एक सस्ता और दुरुस्त समाधान प्रदान करेगी। जिससे दैनिक यात्रियों की पर्याप्त संख्या का समायोजित करते हुए बेहतर फ्रीक्वेंसी और परिचालन दक्षता सुनिश्चित होगी।उन्होंने बताया कि यह कॉरिडोर

केवल ट्रेन की लंबाई को कम करने के बारे में नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयार, कुशल और लागत-समेत मेट्रो प्रणाली के साथ शहरी गतिशीलता के इष्टतम उपयोग करने के बारे में है। लाजपत नगर-साकेत जी ब्लॉक

कोरिडोर को यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। जबकि उच्च घनत्व वाले गलियारों में भारी भीड़ को संभालने के लिए लंबी रैक की आवश्यकता होती है। यह सेक्शन, यात्रियों की एक अलग

कोरिडोर को यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। जबकि उच्च घनत्व वाले गलियारों में भारी भीड़ को संभालने के लिए लंबी रैक की आवश्यकता होती है। यह सेक्शन, यात्रियों की एक अलग

श्रेणी जिसमें कम दूरी के यात्रियों को लगातार और कुशल मेट्रो सेवाओं की आवश्यकता होती है। दयाल ने आगे बताया कि कॉरिडोर के पीक ऑवर पीक डायरेक्शन ट्रैफिक अनुमान मेनेजेबल लोड का संकेत देते हैं।

महावीर जयंती पर दिल्ली विधानसभा में आयोजन



एजेंसी नई दिल्ली। दिल्ली विधान सभा में भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक एवं 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम 'भगवान महावीर गाथा' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में विधानसभा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट उपस्थित रहे। वहीं इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष विजेन्द्र गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भगवान महावीर का जीवन और उनकी शिक्षाएं सम्पूर्ण मानवता के लिए प्रकाशपूर्ण हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रसंत परमाचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर मुनिराज ने कहा कि भगवान महावीर का संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक है। जब समाज को शांति, सहिष्णुता और करुणा की अत्यधिक आवश्यकता है। इसी क्रम में विजेन्द्र गुप्ता ने कहा कि 'महावीर गाथा' जैसे आयोजनों से हमारी सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम मिलता है। उन्होंने कहा, 'महावीर स्वामी का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय और सामाजिक विकास का आधार है। हमें उनके सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर एक शांतिपूर्ण और समरस समाज की ओर बढ़ना चाहिए।

भारतीय ज्ञान, संस्कार एवं समृद्धि की संवाहक है संस्कृत : डॉ चांद किरण सलूजा

एजेंसी नई दिल्ली। भारतीय शिक्षण मंडल का 56वां स्थापना दिवस दिल्ली प्रान्त द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के सत्यवती महाविद्यालय में मनाया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय संगठन मंत्री बी. आर. शंकरानन्द, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो महेश वर्मा, प्रो धनंजय जोशी, प्रो रवि प्रकाश टेकचंदानी, गणपति तेती, ऋषि मोहन भटनागर, सचिन मारण, राजन चोपड़ा, प्रो दर्शन पांडेय सहित सैकड़ों गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।कार्यक्रम में 'शिक्षा में संस्कृत, संस्कृत से संस्कार, संस्कार से समृद्धि' विषयक कार्यक्रम में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. मुरली मनोहर पाठक ने संस्कृत को तीन दृष्टि में समझते हुए कहा कि सृष्टि के साथ ही संस्कृत की उत्पत्ति हुई है 7 उन्होंने अनुशासन एवं

समर्पण को शिक्षा के लिए प्रमुख बताया और संस्कृत एवं संस्कार को एक दूसरे का पर्याय मानते हुए कहा

नीति पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है मानवता को निर्माण करना।उन्होंने मनुष्य के



कि संस्कृत ही हमें विद्या का संस्कार देती है। कार्यक्रम में मौजूद शिक्षक डॉ चांद किरण सलूजा ने कहा कि प्राचीन भारत में शिक्षा का अर्थ मुख्य रूप से भाषा के अर्थ में लिया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करके बेहतर मानव बनना है।उन्होंने शिक्षा

सम्पूर्ण विकास की दिशाओं का वर्णन भी किया।आगे उन्होंने कहा कि हमारा सम्पूर्ण व्यक्तित्व हम से जुड़ा है, साथ ही उन्होंने पंच कोष के माध्यम से संस्कारित जीवन की बात करते हुए वैयक्तितता से सामाजिकता की ओर जाना ही संस्कार बताया।

संपादक की कलम से

भ्रष्टाचार रोकेगी न्यायधीशो की सहमति

भारत में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई ताकत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना तय कर लिया है तो निश्चित तौर पर यह कहा जाए कि अब केन्द्र एवं राज्य सरकार के अफसरानों से लेकर मुलाजिमों तक को अपनी सम्पत्ति का ब्यौरा देना ही पड़ेगा। हालांकि अभी सम्पत्ति का ब्यौरा अफसर और मुलाजिम अपनी जानकारी के अनुसार दे रहे हैं लेकिन दर सबेर उस ब्यौरे की क्रास चेकिंग या जांच का निर्णय भी सरकार द्वारा लिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीशों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने पर जो सहमति जताई है, उसके पीछे कारण चाहे जो भी हो, वह सही दिशा में उठाया गया वाजिब कदम है। इससे न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी और आम लोगों का उस पर भरोसा मजबूत होगा।निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसी संस्था के रूप में देखा जाता है, जो आम लोगों के लिए न्याय की आखिरी उम्मीद है। फिर भी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर जली हुई नोटों की गड्ढी मिलने जैसी घटनाओं और उनसे उपजे विवादों से कहीं न कहीं कुछ संदेह भी बनता है। जस्टिस वर्मा के मामले में नौकरशाहों, कतिपय न्यायधीशों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों के साथ इंजीनियर, मीडिया आदि से जुड़े ऐसे व्यक्ति विशेष जिन्होंने आकृत सम्पत्ति विभिन्न गैरवाजिब तरीके से जुटा रखी है उन पर शिकंजा कसना तय है। यह बात अलग है कि इसके परिणाम कुछ देर से आएंगें क्योंकि भ्रष्टाचार अभी भी चरम पर है। सभी जानते हैं कि पिछले लगभग तीन दशक में, यह मामला कई बार उठा है। सूचना का अधिकार लागू होने के बाद यह बहस भी हुई कि न्यायपालिका इसके दायरे में क्यों नहीं। इसके पीछे यही तर्क रहा कि किसी निजी जानकारी को तब तक साझा करने की जरूरत नहीं, जब तक उससे सार्वजनिक हित न जुड़े हों। 2010 और 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में यह केस आया था, तब इसी नुस्ते को आधार बनाकर कहा गया कि जानकारी सार्वजनिक करना न्यायाधीशों की इच्छा पर है।सरकार की एक संसदीय समिति ने 2023 में सिफारिश की थी कि न्यायाधीशों के लिए संपत्ति की घोषणा अनिवार्य की जाए। हालांकि सरकार इस मामले में आगे नहीं बढ़ी और बाद में कहा कि उसका ऐसा कोई इरवादा भी नहीं है। यह रुख गलत नहीं कहा जा सकता। सरकार की तरफ से किया गया कोई भी प्रयास यह संदेश देता कि न्यायपालिका में अनावश्यक राजनीतिक दखल हो रहा है। न्यायपालिका की साख के लिए उसका स्वतंत्र होना और दिखना भी उतना ही जरूरी है। हालांकि यह कदम काफी नहीं है। न्यायपालिका के कामकाज में कई तरह की गड़बड़ियां हैं। कई स्तरों पर न्यायिक सुधार के प्रयास आगे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन इस कदम से एक पॉजिटिव संदेश जरूर गया है कि सर्वोच्च अदालत के जज खुद को भी उन कसौटियों पर कसने में नहीं हिचकते जिन्हें वे दूसरों के लिए जरूरी मानते हैं। ज्ञात हो कि 15 फरवरी 2018 को चुनाव सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने कानून मंत्रालय से इस बात के लिए नाराजगी जताई है कि उसने आदेश के बावजूद पिछले कुछ वर्षों में उम्मीदवारों की संपत्ति में आय से अधिक वृद्धि को ट्रैक करने के लिए एक त्थायी तंत्र क्यों नहीं बनाया. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी जारी कर दो हफ्ते में विधायी विभाग के सचिव से जवाब देने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछ था कि फार्म 26 में वो घोषणा शामिल क्यों नहीं की गई है जिसके तहत उम्मीदवार को बताना होता है कि वह जनप्रतिनिधित्व कानून के किसी प्रावधान के तहत अयोग्य नहीं है।सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें लोकप्रहरी संस्था द्वारा दाखिल अमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान कहीं थी। यानि कि एक लम्बे अरसे से विभिन्न संवर्ग के मामले में आय से अधिक सम्पत्ति के मामले सामने आने तथा इनका सीधा सरोकार भ्रष्टाचार से होने के कारण यह मामला सीधे लोकतंत्र को सुचिता से जुड़ा हुआ है। चंद दिनों पूर्व जज श्री वर्मा के यहा करोड़ों रुपए की नागदी के जलने का मामला सामने के बाद न्यायपालिका पर उठे सवाल के उपरान्त न्यायधीशों द्वारा सम्पत्ति का विवरण देने सहमति वाकई अगले कुछ सालों में अपना रंग दिखायेगी। हालांकि ब्यौरा देने में अभी इतने हाल है कि उनको भरने में समय लगेगा लेकिन दर सबेर इसका निर्णय सुखद होगा।

क होने के बाद दोबारा क्यों हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर? एक्सपर्ट ने बताया



बॉलीवुड अभिनेता आधुमान खुराना की पत्नी तारिया कश्यप को दूसरी बार ब्रेस्ट कैंसर हो गया है. सात साल पहले भी उनको ये बीमारी हुई थी और वह ठीक हो गई थी, लेकिन फिर से कैंसर हो गया है. कई मामलों में ये बीमारी दूसरी बार भी हो जाती है, लेकिन इसका कारण क्या है? इस बारे में एक्सपर्ट्स से जानते हैं. कैंसर सर्जन डॉ अंशुमान कुमार बताते हैं कि कुछ मामलों में ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर की कुछ सेल्स बची हुई रह जाती हैं. वह कुछ समय बाद दोबारा बढ़ने लगती हैं इससे कैंसर हो जाता है. अगर ब्रेस्ट में नए कैंसर की उत्पत्ति होती है, तो यह दोबारा ब्रेस्ट कैंसर का कारण बन सकता है. कुछ महिलाओं में हार्मोनल प्रभाव ब्रेस्ट कैंसर फिर से होने का कारण बनते हैं. अगर महिला के परिवार में पहले किसी को ये बीमारी रही है तो जेनेटिक कारणों की वजह से दोबारा कैंसर हो जाता है. इस तरह के मामले सामने आते भी हैं. अगर कैंसर के इलाज के बाद किसी महिला ने अपनी लाइफस्टाइल फिर से खराब कर ली है और खानपान की आदतें बिगड़ गई हैं तो ये बीमारी दोबारा से हो सकती है.

क्या दोबारा हुआ कैंसर ज्यादा खतरनाक होता है?

डॉ. अंशुमान बताते हैं कि दोबारा हुआ कैंसर ज्यादा खतरनाक हो भी सकता है और नहीं भी, यह कई कारकों चीजों पर निर्भर करता है. दोबारा हुआ कैंसर का प्रकार पहले हुए कैंसर के प्रकार से अलग हुआ तो ज्यादा खतरनाक हो सकता है. ये भी देखना होता है कि इस बार के कैंसर की पहचान कौन सी स्टेज में हुई है.

अगर दूसरी बार का कैंसर एडवांस स्टेज का है तो यह ज्यादा खतरनाक हो सकता है. कुछ मामलों में कैंसर के लिए उपचार के विकल्प रहते हुए कैंसर के उपचार से अलग हो सकते हैं. दोबारा हुआ कैंसर रोगी को सेहत पर निर्भर करता है कि उसकी इम्युनिटी कैसी है. अगर इम्युनिटी हल्की होगी तो खतरा अधिक हो सकता है. ऐसे में अगर किसी को दूसरी बार ये बीमारी हुई है तो विशेष देखभाल की जरूरत हो सकती है.

संपादकीय

दिशाहीन भीड़ की मानसिकता से समाज को सर्वाधिक खतरा

संजीव

सामाजिक सरोकार के परिवर्तन और उसके विरोध से उठे सवालों से सहमति और असहमति से उपजे असंतोष से भिड़ तंत्र द्वारा हिंसक अहिंसक प्रदर्शन से मानवता और सामाजिक एकरसता को सबसे बड़ा खतरा जन्म लेता जा रहा है यह राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर चिंतन का विषय बन चुका है। आज देश के लगभग अधिकतर राज्यों में चुनाव की प्रतिस्पर्धा और धार्मिक उन्माद से जल रहे हैं। मानवता चीत्कार कर रही है और आम नागरिक अपने जलते हुए घरों और परिवजनों के मृत शव को देखकर भयभीत हो रहे हैं। मणिपुर, पश्चिम बंगाल और संभल की हिंसात्मक घटनाओं को देखकर धीरे-धीरे सामाजिक न्याय पर विश्वास उठता जा रहा है जब मंत्रियों और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के घरों में आग लगाई जा सकती है तो आम आदमी कि कोई अहमियत नहीं रह गई है। राज्य सरकारें हाथ में हाथ धरे बैठी केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है बड़ी विभीषिका के दृश्य सामने आ रहे हैं। भीड़ तंत्र द्वारा किया गया न्याय राज्य की विफलता है। जो कार्य राज्य की कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा गुण दोष के आधार पर किया जाना चाहिए, आज उसे भीड़ तंत्र द्वारा किया जा रहा है, यह सार्वभौमिक अवधारणा है कि भीड़ को राजनीति और सत्ता मिलकर पैदा करते हैं, और यही सामूहिक कार्यों की भीड़ राज्य के नियंत्रण से मुक्त होकर राज्य के अस्तित्व को चुनौती देने लगती है। और फिर सामने आती है माब लीचिंग। वर्तमान समाज उपभोक्तावादी हो गया है,आजकल सहयोग तथा सहिष्णुता की भावना तथा समझ लगातार कम होते जा रही है। हम की संयुक्त भावनाओं के बजाए मैं की प्रवृत्ति सामने आने लगी है । और समाज व्यक्ति केंद्रित विकास की ओर अग्रसर हो कर समाज का एक बड़ा तबका विकास

ट्रम्प-मस्क के खिलाफ अमेरिका

जिस डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरी बार जीतकर आने के बाद उनके शपथ ग्रहण समारोह में न्यौता पाने के लिये भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उसुकु थे और तत्काल बाद वगैर कोई खास अवसर के अमेरिका पहुंचकर उनसे मिल आये थे, उन्हीं ट्रम्प महाशय के खिलाफ अमेरिका की जनता सड़कों पर है। ये वे ही लोग हैं जिन्होंने उन्हें दूसरी बार दुनिया के सबसे ताकतवर देश की गद्दी सौंपी थी तथा इन्हीं के भरोसे ट्रम्प तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिये वहां के संविधान में संशोधन तक लाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां के शनिवार (5 अप्रैल) को उनके खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया गया जो हाल के वर्षों का उस देश का सबसे बड़ा जन प्रदर्शन रहा। अमेरिकी नागरिक मानने लगे हैं कि उन्होंने ट्रम्प को चुनकर बड़ी गलती की है। मुख्य वजह है ट्रम्प की नीतियां जिनके बारे में वे कह रहे हैं कि इससे अमेरिका दुनिया भर में अपने सहयोगियों को खो रहा है। उनकी टैरिफ नीति के साथ सामाजिक सुरक्षा पर आसन खतरों को लेकर वे बेहद गुस्से में हैं। दुनिया के सबसे अमीर एलन मस्क भी जनता के निशाने पर आ गये हैं जिन्होंने ट्रम्प के प्रचार अभियान को तो सम्हाला ही था, ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के बाद एक तरह से वे प्रशासन में खाममखास हैं। ट्रम्प ने उन्हें डीओजीई यानी सरकारी दक्षता विभाग का प्रमुख बना दिया है जो प्रशासन कर्मचारियों की बड़ी संख्या में कटौती करने का इरादा जाहिर कर चुके हैं। यह अलग बात है कि उन्होंने हाल ही में यह पद जल्दी छोड़ देने का ऐलान किया है। तो भी, ट्रम्प की नीतियों पर मस्क का कहा बहुत चलता है। वे पद छोड़ भी दें तो भी उनका प्रभाव बना रहेगा। इस विशाल देश के सभी 50 राज्यों में 1400 से ज्यादा स्थानों पर ट्रम्प और एलन मस्क की नीतियों के विरोध में प्रदर्शन हुए जिनमें हजारों के आदि शामिल थे। यह प्रदर्शन पूर्णतः शांतिपूर्ण रहा। किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी को मिली सफलता के बाद ट्रम्प को राष्ट्रपति का पद सम्हाले अभी तीन माह भी नहीं हुए हैं, पर उनके कामकाज के तरीकों ने पूरे अमेरिका को नाराज कर दिया है। उनके कामों का प्रतिकूल असर न सिर्फ देश के भीतर वरन विश्व भर में पड़ने की सम्भावना है। खासकर उनकी टैरिफ नीति से, जिसे ट्रम्प द्वारा दुनिया भर के खिलाफ छोड़ा गया 'टैरिफ वॉर' कहा जा रहा है, अमेरिका को बड़ा नुकसान होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। अमेरिका में आप्रवासियों को जिस तरह से बाहर निकाला गया उससे भी लोगों में नाराजगी है क्योंकि ट्रम्प अपने दूसरे कार्यकाल में भेदभाव की नीति अपना रहे हैं। उन्होंने अपने देश में क्रूर पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने की जो नीति अपनाई है वह उनके अपने लोगों को इसलिये नहीं भा रही है क्योंकि उससे बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां जा सकती हैं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बजट में कटौतियां सम्भव हैं। इससे उनके जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आधे दशक से भी ज्यादा की अवधि में दुनिया भर में कई अनावश्यक निर्मित सैन्य मोर्चों पर, विशेषकर शीत युद्ध के दौरान अपने हजारों नागरिकों के प्राण गंवाने वाले अमेरिकियों को ट्रम्प की भड़काऊ व उकसाने वाली नीतियां रास नहीं आ रही हैं।



के पथ से बहुत पीछे छूट गया है। वस्तुतः एक तरफा वैश्वीकरण तथा साधनों के केंद्रीकरण के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी खुलकर सामने आने लगी है। भारत के 10% लोगों के पास देश की 58% संपत्ति का स्वामित्व है। एवं देश की पूंजी का 70% भाग 1 प्रतिशत लोगों के अधिकार क्षेत्र में है। यही कारण है कि भारत में भी फ्रांस एवं रूस की क्रांति जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस मामले में भारत में हर राज्य की भूमिका अलग-अलग तथा भिन्न भिन्न है। भारत की शिक्षा व्यवस्था भी भीड़ तंत्र को काफी प्रोत्साहित कर रही। बैचलर डिग्री तथा मास्टर डिग्री लेने के बाद डिग्री धारी लोग बेरोजगारी या अल्प रोजगार के कारण कुटिंत हो रहे हैं। और यही कुंठा बेरोजगारी एवं गरीबी किसी भी घटना को भीड़ तंत्र की ओर खींचती है, फल स्वरूप माँब लीचिंग की अनेक घटनाएं

सामने आने लगी हैं। दूसरी तरफ कानून का यह मानना है कि न्याय में विलंब न्याय को नकारना है। भारत की न्याय व्यवस्था अपने लंबित मुकदमों तथा प्रकरण के कारण एक तरह से अन्याय को ही जन्म देती है। किसी हथियारे या बलात्कारी को सजा देने का समय तब आता है, जब आरोपी बहुत बुजुर्ग अथवा मर चुका होता है। भीड़ तंत्र अस्थायी रूप से समान मूल्यों तथा भावनाओं की पहचान के साथ जुड़े अलग-अलग समूहों के लोगों का शामिल एक बड़ा समूह है। भीड़ की कोई अपनी आँख शक्ल नहीं होती एवं भीड़ की कोई पहचान भी नहीं होती है। इसके उद्देश्य तत्कालिक होते हैं, यह भी हो सकता है कि भीड़ में जो एक क्षण पहले नायक हुआ करता था, वह अगले ही पल उस समूह का पीड़ित व्यक्ति भी हो सकता है। इतिहास में इसके कई उदाहरण है

जहां भीड़ ने अपने नेता को पद से हटाकर उसकी विनाश लीला ही रचा दी थी। फ्रांस का शासक रोबेस्पीयर इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सिगमंड फ्रायड के अनुसार भीड़ में व्यक्ति अपने सारे मूल्य खोकर आदिम काल में पहुंच जाता है, और भीड़ में कोई धर्म नहीं रह जाता है। कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की लेटलतीफी के कारण भीड़ को कानून का भय लगभग समाप्त हो गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन कर किसी विशेष धर्म के लोगों को खानपान तथा व्यंजन के आधार पर कथित लोगों द्वारा किसी को भी निशाना बना कर उसकी हत्या कर दी जाती है, यह देश के लिए अत्यंत दुर्भाग्य जनक है। रही सही कसर सोशल मीडिया पूरा कर रहा है, फर्जी समाचार तथा राजनीतिक नियंत्रण के कारण

सोशल मीडिया कई बार किसी विशेष वर्ग के द्वारा राजनीतिक संरक्षण में संचालित किया जा रहा है। लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा चौथा स्तंभ मीडिया भी जन जागरूकता के प्रचार प्रसार के बजाय घटनाओं को धर्म तथा वर्ग के आधार पर विशेष वर्ग के हितों को प्रचारित प्रसारित करता है, जो इस आदिम कॉल की व्यवस्था को पुष्पित पल्लवित करता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रयोग सामाजिक विकास न्याय के स्थान पर अन्याय प्रकृति की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। माँब लीचिंग के कारण समाज में आम हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगी है,इससे समाज की संस्कृति को दीर्घकालिक क्षति होगी। इस तरह भीड़ तंत्र के द्वारा की गई हिंसक घटनाओं तथा हत्या से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की साख की गिरावट भी होती है, एवं आर्थिक क्षेत्र में निवेश पर विपरीत

प्रभाव पड़ता है। इसी तरह हिंसक घटनाओं से पलायन तथा संसाधनों के विकास पर बाधा पड़ने से सामाजिक तथा आर्थिक क्षमता को बढ़ावा मिलता है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम भी सामूहिक भीड़ के माध्यम से ही जीता था,फ्रांस तथा रूस में भी भीड़ द्वारा सकारात्मक भूमिका निभाकर अनेकित तथा अवैधानिक शासन तंत्र को खत्म किया था। भीड़ तंत्र द्वारा ही करप्शन अगेंस्ट इंडिया चलाकर का भी कुछ सफलता प्राप्त की थी।पर इस भीड़ तंत्र के न्याय की नकारात्मक भूमिका आज की स्थिति में ज्यादा है। अतः हमें इसे प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। भीड़ तंत्र तथा माँब लीचिंग को एक घनघोर सामाजिक बुराई समझकर सामाजिक संगठनों नागरिकों एवं शासन तंत्र द्वारा एक अभियान चलाकर ऐसे लोगों को हतोत्साहित कर कठोर कानून बनाकर इसे

जंगलों पर छया इंसानों का आतंक

प्रियंका सौरभ

हाल ही में एक अखबार की प्रमुख हेडलाइन पढ़ी-"शहर में बंदरों और कुत्तों का आतंक"। यह वाक्य महज एक खबर नहीं, बल्कि हमारे सोचने के तरीके का प्रतिबिंब था। हमने जानवरों के शहर में आने को "आतंक" करार दिया, लेकिन कभी यह सवाल नहीं पूछा कि वो शहर में आए ही क्यों जब कोई बंदर किसी कॉलोनी की छत पर उछलता है, या कोई कुत्ता कूड़े के ढेर में भोजन तलाशता है, तो वह कोई स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं होती। यह उस संकट का संकेत होता है जिसे हम-मनुष्य-ने स्वयं गढ़ा है। जंगल, जो कभी इन जीवों का घर थे, अब रियल एस्टेट की परियोजनाओं, खनन कार्यों, सड़कों और डैमों की बलि चढ़ चुके हैं। आज अगर कोई सच में आतंक फैला रहा है, तो वह है इंसानी लालच और विकास का अंधा मॉडल। प्राकृतिक आवासों पर हमला भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जहाँ जैव विविधता है अद्भुत संपदा है। लेकिन यही भारत आज अपने ही जंगलों को खा रहा है। 2021 की *वर्ल्ड राइस र४१५ीट* द्वा *वर्ल्ड रिपोर्ट* बताती है कि भारत ने पिछले चार वर्षों में 1,100 वर्ग किलोमीटर से अधिक वनक्षेत्र खो दिया है। हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा जैसे राज्यों में यह गिरावट विशेष रूप से चिंताजनक है। वन कटान केवल पेड़ों का नुकसान नहीं है। यह पूरी एक पारिस्थितिकी व्यवस्था का ध्वंस है। जब हम पेड़ काटते हैं, हम न सिर्फ ऑक्सीजन के स्रोत मिटाते हैं, बल्कि हजारों पशु-पक्षियों के घर उजाड़ देते हैं। यही कारण है कि आज हमें गाँवों और शहरों के



आसपास बाघ, हाथी, भालू और यहाँ तक कि तेंदुए भी दिखने लगे हैं। और हम पीड़ित। शहरों में जानवरों की बढ़ती उपस्थिति: एक चेतावनी बंदरों का शहरों में आना आज एक आम दृश्य बन गया है। दिल्ली, वाराणसी, जयपुर, और देहरादून जैसे शहरों में बंदरों की आबादी तेजी से बढ़ी है। कारण स्पष्ट हैं-कम होती हरियाली, अधिक होता कूड़ा, और बिगड़ता पारिस्थितिक संतुलन। इसी तरह, आवारा कुत्तों की संख्या भी शहरों में नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। अनुसार भारत में लगभग 3.5 करोड़ आवारा कुत्ते हैं, और हर साल हजारों लोग कुत्तों के काटने के शिकार होते हैं। मगर यह समस्या केवल स्वास्थ्य या सुरक्षा की नहीं है; यह समस्या हमारे कुप्रबंधन और लापरवाह विकास की है। हमने कूड़ा फेंकने के तरीकों को सुधारा नहीं, सार्वजनिक पशु-नियंत्रण कार्यक्रमों को प्राथमिकता नहीं दी, और अब जब जानवर हमारी बस्तियों में दिखते हैं, तो उन्हें "संकट" कह कर खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं। जब कोई अखबार लिखता है कि "बंदरों का आतंक", तो वह केवल सूचना नहीं दे रहा होता, बल्कि एक धारणा गढ़ रहा होता

है। यह धारणा कि जानवर आक्रमणकारी हैं। और हम पीड़ित। मीडिया की यही भाषा यह छिपा लेती है कि असल में हम ही उनके घरों में घुसे थे, उनकी जमीन छीनी, और अब जब वो अपनी जगह पाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें दोषी ठहराते हैं। यह भाषा केवल संवेदनहीन नहीं, बल्कि खतरनाक भी है, क्योंकि इससे संरक्षण के प्रति समाज की समझ और सहानुभूति दोनों कमजोर पड़ती हैं। **वन्यजीव संघर्ष: क्यों बढ़ रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार**, भारत में हर साल औसतन 100 से अधिक लोग हाथियों के हमलों में मारे जाते हैं, और दर्जनों बाघ-मानव संघर्ष की घटनाएँ सामने आती हैं। मगर इन घटनाओं के पीछे की सच्चाई यह है कि वन्यजीवों का घर सिकुड़ता जा रहा है। जंगलों में भोजन और पानी की कमी उन्हें मानव बस्तियों की ओर खींचती है। कभी-कभी वे रास्ता भटक जाते हैं, तो कभी उन्हें मजबूरी में खेतों और घरों में घुसना पड़ता है। यह संघर्ष उनके लिए भी घातक है-हर साल सैकड़ों जानवर इंसानी जवाबी हिंसा में मारे जाते हैं। **क्या हो सकता है समाधान**

वन विभाग अक्सर संसाधनों और जनबल की कमी से जूझता है। इसके अलावा, जब विकास परियोजनाओं और वन्यजीव संरक्षण में टकराव होता है, तो अक्सर विकास को तरजीह दी जाती है, भले ही उसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी हों। इस संकट से उबरने के लिए केवल नीतियाँ नहीं, बल्कि सोच का परिवर्तन जरूरी है। कुछ संभावित उपाय इस प्रकार हैं: शहरी नियोजन में हरित क्षेत्र सुनिश्चित किया जाए – पार्क, बाग-बगिचे, और वृक्षारोपण को केवल सजावटी पहलू नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी के हिस्से के रूप में देखा जाए। वन्यजीव गलियारे (*द एनिल ड्र४११ड्रि४२*) विकसित किए जाएँ – जिससे जानवरों को सुरक्षित आवागमन का रास्ता मिले। कचरा प्रबंधन को प्राथमिकता दी जाए – ताकि जानवर शहरी कूड़े पर निर्भर न हों। मीडिया और शिक्षा में संवेदनशीलता लाई जाए – जानवरों को 'आतंकवादी' बताने के बजाय उनके संघर्ष को समझने और सहानुभूति की भाषा अपनाई जाए। स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाए – उन्हें संरक्षण के साझेदार बनाना होगा, विरोधी नहीं। **अंतिम बात: इंसान अकेला नहीं है इस धरती पर** हमें यह स्वीकार करना होगा कि यह धरती केवल हमारी नहीं है। जंगलों, नदियों, पहाड़ों, और समंदरों के साथ-साथ हर जीव-जंतु का इस पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। जब हम शहरों का विस्तार करते हैं, जब हम मॉल और एक्सप्रेसवे बनाते हैं, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी न किसी की जमीन छीनी जा रही है।

अमेरिका में खसरे से एक और बच्चे की मौत, एक लापरवाही पड़ रही भारी



विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें लोग ट्रंप-मस्क गो बैक के नारे लगा रहे हैं।

क्या है विरोध की वजह?

ट्रंप के खिलाफ यह विरोध उनकी टैरिफ नीति के कारण हो रहे छटनी, आर्थिक मंदी और मानवाधिकार उल्लंघन जैसे मुद्दों पर हो रहा है।

पहले जहाँ ट्रंप के दूसरे बार राष्ट्रपति बनने पर अमेरिकी जनता ने जश्न मनाया था वहीं अब सिविल राइड्स, रफ्त, श्रमिक संघ, एलजीबीटीक्यू समुदाय और महिला अधिकार संगठन ट्रंप की नीतियों का विरोध करने सड़कों पर उतरे हैं।

इजराइल ने गाजा के 50 प्रतिशत हिस्से पर किया कब्जा, फिलीस्तीनियों के लिए लौटना असंभव

इंटरनेशनल डेस्क. हमास के खिलाफ पिछले महीने युद्ध फिर से शुरू करने के बाद से इजराइल ने गाजा पट्टी में अपने प्रभाव का तेजी से विस्तार किया है और अब वहां 50	हमले के बाद यह युद्ध शुरू हुआ था। बहरहाल, मानवाधिकार समूहों और गाजा संबंधी मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि इजराइल के कब्जे वाली भूमि में क्षेत्र के उत्तर को दक्षिण से
---	--



इजराइल का कहना है कि उसकी कार्रवाई अस्थायी रूप से जरूरी है ताकि सार्वजनिक सुरक्षा 2023 को हुए हमले के दौरान बंधक बनाए गए शेष लोगों को रिहा करने के लिए हमारा परादाव बनकर जा सके। हमारा द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा 2023 को किए गए

जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने पिछले साप्ताहिक था कि हमस की हार के बाद भी इजराइल गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखेगा और फलस्तीनियों को वहां से जाने के लिए मजबूर करेगा। इजराइल के पांच सैनिकों ने

**कनाडा ने अमेरिका को दिखाई सख्ती!
विदेश मंत्री मेलानी जोली का बड़ा ऐलान**

इंडरप्रेशनल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ को लेकर कनाडा ने सख्ती दिखाई है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने आज अमेरिका के नए टैरिफ और डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल ट्रेड रीसेट अभियान पर तीखा बयान दिया है। मेलानी जोली ने कहा कि हम अमेरिका द्वारा उठाए गए कदमों का गंभीरता से मूल्यांकन कर रहे हैं। साथ ही, हमें अच्छी तरह से पहचाना गया है कि अमेरिका के साथ हमारा रिश्ता अब कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था।

हैगा जैसा पहले था।
उन्होंने आगे कहा कि हम
अमेरिका के सबसे बड़े ग्राहक हैं।
जब कोई अपने सबसे बड़े ग्राहक के
समक्ष गलत व्यवहार करता है, तो
इसका मतलब होता है कि वह अपनी
पूरी व्यापारिक रणनीति बदलना
चाहता है। अब कानाडी भी अपनी

अमेरिका ने कानाडा समेत कई देशों
से आयात होने वाले उत्पादों पर नया
टैरिफ (आयात शुल्क) लगाए हैं। इसके
साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने न
लम्बेल ट्रेड रीसेट अभियान की
घोषणा की है, जिसका मकसद है
अमेरिकी उद्योगों को विदेशी
प्रतिस्पर्धा से बचाना और व्यापार

वाली है मिलिट्री वार, अमेरिकी टैरिफ पर भ
ने वाली भविष्यवाणी बोला- खतरे में वैश्विक



देश की स्थिति और भूमिका अहम होगी, जिस पर बाबा वेंगा ने अपूर्वानुमान में संकेत दिए हैं। हालाँकि उन्होंने इस देश का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया है, लेकिन उनके अनुयायियों और विशेषज्ञ इस भविष्यवाणी को लेकर कयास लगा रहे हैं कि यह कि

भारतों की नई शुरुआत, राष्ट्रपति

और भारत
मन्त्रियों में,
वॉन डेर
लेज़ेन ऑफ
था। भारत
क व्यापार
मंद जताई
दिवसीय
के बीच
गर्भगंड के
तर्तुगाल की
ममवार की

राष्ट्रपति मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा
और वह पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी



सूसा, प्रधानमंत्री
स्पीकर डॉ. जोस
नेतृत्व के साथ ब
के मेयर कार्लोस
राष्ट्रपति मुर्मू के लि
मेज़बानी करेंगे।
आयोजित भोज
मंत्रालय में शोध
राष्ट्रपति की यात्रा
जानकारी देते हुए
के बीच व्यापार
है और पिछले प



सूसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओ एसेंबली स्पीकर डॉ. जोस पड़े एगुलर-को की सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ बोलोस में आल फेलिस मेगदास राष्ट्रपति मुमू के लिए एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करेगी। वही राष्ट्रपति सूसा द्वारा आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। विशेष मंत्रालय में सचिव (पब्लिक) तमयल लाल ने राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में शुक्रवार को जानकारी दी है वह कह, "भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है और पिछले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ। "हम अगले वर्ष शिक्षा, पर्यटन और विज्ञान के उद्देश्यों के लिए भारत-पुर्तगाल महत्वपूर्ण पर चर्चा लाल ने व पर चर्चा "2000

सूसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओ एसेंबली स्पीकर डॉ. जोस पड़े एगुलर-को की सहित शीर्ष नेतृत्व के साथ बोलोस में आल फेलिस मेगदास राष्ट्रपति मुमू के लिए एक विशेष कार्यक्रम की मेजबानी करेगी। वही राष्ट्रपति सूसा द्वारा आयोजित भोज में भी शामिल होंगे। विशेष मंत्रालय में सचिव (पब्लिक) तमयल लाल ने राष्ट्रपति की यात्रा के बारे में शुक्रवार को जानकारी दी है वह कह, "भारत और पुर्तगाल के बीच व्यापार 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर का है और पिछले पांच वर्षों में 50 प्रतिशत की वृद्धि के साथ। "हम अगले वर्ष शिक्षा, पर्यटन और विज्ञान के उद्देश्यों के लिए भारत-पुर्तगाल महत्वपूर्ण पर चर्चा लाल ने व पर चर्चा "2000

लगातार बढ़ रहा है।उन्होंने कहा, ऊर्जा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग में हैं।

हाथ भी कहा कि पुर्तगाल ने हमेशा संघ साझेदारी को गहरा करने में मदद किया है।

यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में संभावना के बारे में पूछे जाने पर था, 'हां, आपसी हितों के क्षेत्रों में जाड़ीगी। हालांति ने कहा था, पुर्तगाल के राष्ट्रपति द्वारा पहला

लगातार बढ़ रहा है।उन्होंने कहा, ऊर्जा, आईटी, फार्मास्यूटिकल्स, और रक्षा के क्षेत्र में सहयोग में हैं।

हाथ भी कहा कि पुर्तगाल ने हमेशा संघ साझेदारी को गहरा करने में मदद किया है।

यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते में संभावना के बारे में पूछे जाने पर था, 'हां, आपसी हितों के क्षेत्रों में जाड़ीगी। हालांति ने कहा था, पुर्तगाल के राष्ट्रपति द्वारा पहला

यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित गया था।

साथ ही 2021 में, भारत और यूरोपीय संघ नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन जिसमें यूरोपीय संघ के सभी भागीदार नेताओं ने भाग लिया।

इसलिए भारत-पुर्तगाल संबंधों में भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का एक बहुत मजबूत पहलू है। पुर्तगाल की अपनी यात्रा के दौरान मुमू विभिन्न पुर्तगाली संस्थानों में शोधकर्ताओं सहित भारतीय सुपुर्वाह दलों के साथ बातचीत करेगी।

यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन आयोजित गया था।

साथ ही 2021 में, भारत और यूरोपीय संघ नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन जिसमें यूरोपीय संघ के सभी भागीदार नेताओं ने भाग लिया।

इसलिए भारत-पुर्तगाल संबंधों में भारत-यूरोपीय संघ साझेदारी का एक बहुत मजबूत पहलू है। पुर्तगाल की अपनी यात्रा के दौरान मुमू विभिन्न पुर्तगाली संस्थानों में शोधकर्ताओं सहित भारतीय सुपुर्वाह दलों के साथ बातचीत करेगी।

कताइब हिज्रुब्रह्म के पास करीब 30 हजार लड़के हैं, ये संगठन इराक और ईरान में सक्रिय हैं। इसे ईरान से ही संजोना भी मिलती है। इसी तरह नुज्बा के पास 10 हजार लड़के हैं। बाकी के 4 संगठनों के पास भी करीब 20 हजार लड़के हैं। अगर कुल जोड़ देखा जाए तो इसकी संख्या 60 हजार के आसपास है। ऐसे में पहले जा रहा है कि जंग शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से इन संगठनों से संपर्क करने का सूत्र अपनाया है, उससे ईरान को झटका लग सकता है।

कताइब हिज्रुब्रह्म के पास करीब 30 हजार लड़के हैं, ये संगठन इराक और ईरान में सक्रिय हैं। इसे ईरान से ही संजोचना मिलती है। इसी तरह नुज्बा के पास 10 हजार लड़के हैं। बाकी के 4 संगठनों के पास भी करीब 20 हजार लड़के हैं। अगर कुल जोड़ देखा जाए तो इसकी संख्या 60 हजार के आसपास है। ऐसे में पहले जा रहा है कि जंग शुरू होने से पहले ही जिस तरीके से इन संगठनों से संपर्क करने का सूत्र अपनाया है, उससे ईरान को झटका लग सकता है।

कैसे

रश्मिका मंदाना

ने नेशनल क्रश से लेकर
पैन-इंडिया स्टार तक पूरे
देश में जीता दिल

विरासत से भरी दुनिया में, रश्मिका मंदाना ने कड़ी मेहनत, समर्पण और अपार प्रतिभा के साथ अपना रास्ता बनाया है, और भारत की सबसे पसंदीदा सितारों में से एक बन गई हैं। उनका स्टारडम सीमाओं को पार करता है, पूरे देश में हर घर तक पहुंचता है और अकल्पनीय ऊंचाइयों को छूता है। कूर्ग की एक छोटे शहर की लड़की से, जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन बड़े सपने थे, वह सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई है। अभिनेत्री आज अपने करियर में बड़ी उपलब्धियों के साथ एक साल और बड़ी हो गई है और आने वाले समय में और भी बहुत कुछ हासिल करने वाली है। जैसा कि वह जीवन का एक और वर्ष मनाती है, आइए उसकी अविश्वसनीय और प्रेरक यात्रा पर एक नज़र डालें। रश्मिका मंदाना ने 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, जो एक बड़ी हिट साबित हुई। उनकी आकर्षक ऑन-स्क्रीन उपस्थिति, स्वाभाविक अभिनय कौशल और निर्विवाद आकर्षण ने दक्षिण भारतीय सिनेमा के दर्शकों और फिल्म निर्माताओं का दिल जीत लिया। उन्होंने तेलुगु और कन्नड़ दोनों उद्योगों में सहजता से कदम रखा और लगातार दो ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं। गीता गोविंदम और डिंयर कॉमरेड जैसी प्रतिष्ठित फिल्मों के साथ, उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा में एक भरोसेमंद सुपरस्टार और एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की हालांकि, रश्मिका को सबसे बड़ी सफलता पुष्पा: द राइज़ से मिली, जिसमें उन्होंने अल्लु अर्जुन के साथ प्रतिष्ठित श्रीवल्ली की भूमिका निभाई। यह फिल्म एक बड़ी अखिल भारतीय ब्लॉकबस्टर बन गई, जिसने उन्हें देश भर में प्रसिद्धि दिलाई। उनके अभिनय की व्यापक रूप से सराहना की गई, लेकिन यह उनका विद्युतीय गीत सामी सामी था जो एक वायरल सनसनी बन गया, जिसने उन्हें एक सच्चे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित किया। अपने सहज आकर्षण और भाषाई और क्षेत्रीय बाधाओं से परे दर्शकों से जुड़ने की क्षमता के साथ, वह सबसे अधिक मांग वाले सितारों में से एक बन गई।



रश्मिका मंदाना ने अमिताभ बच्चन के साथ गुडबाय में अपनी शुरुआत के साथ बॉलीवुड में अपनी जगह बनाई, जो उनके हिंदी फिल्मी सफर की शुरुआत थी। बाद में उन्होंने ब्लॉकबस्टर एनिमल में अभिनय किया, जिसमें उनकी अविश्वसनीय बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और उनके प्रशंसक आधार का और विस्तार किया। उनकी संक्रामक ऊर्जा, विनम्रता और सापेक्षता ने उन्हें आज सबसे अधिक पसंद की जाने वाली हस्तियों में से एक बना दिया है। हाल ही में, उन्होंने छावा में दर्शकों को प्रभावित किया, जहाँ उन्होंने एक भयंकर मराठा रानी का किरदार निभाया, और सिकंदर में सलमान खान के साथ भी अभिनय किया। चाहे हिंदी हो, तेलुगु, कन्नड़ या तमिल सिनेमा, उन्होंने हर जगह दर्शकों को प्रभावित किया है। उनके बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया फैन्डम उनकी अपार लोकप्रियता को दर्शाता है, क्योंकि वह प्रशंसकों के साथ खुलकर बातचीत और सशक्त संदेशों के माध्यम से जुड़ती हैं।

जूता चुराई की रसम में क्यों आया था

कैटरीना कैफ

को गुस्सा? विक्की कौशल ने शेयर किया शादी का मजेदार किस्सा

2021 में एक शादी काफी चर्चा में थी और वो विक्की कौशल-कैटरीना कैफ की शादी थी. इस शादी के बारे में किसी को लास्ट मोमेंट तक भनक नहीं लगी, सिर्फ अफवाहें थीं कि उनका अफेयर चल रहा है लेकिन जब शादी की तैयारियां शुरू हुईं तो लोगों ने कयास लगाए और फिर 9 दिसंबर 2021 को विक्की-कैटरीना ने शादी कर ली. इस शादी में जूता चुराई रसम के दौरान कैटरीना कैफ को गुस्सा आ गया था लेकिन इसकी वजह क्या थी ? फिल्म गोविंदा आला रे (2022) के प्रमोशन के लिए विक्की कौशल-कियारा आडवाणी के साथ 'द कपिल शर्मा शो' में पहुंचे थे. इस दौरान जब कपिल शर्मा ने जूता चुराई रसम के बारे में विक्की से पूछा तो एक्टर ने एक मजेदार किस्सा सुनाया, आइए जानते हैं वो क्या था ?

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी
शो में कपिल शर्मा ने पूछा, 'विक्की पाजी एक बात बताओ, कैटरीना की 6 बहने हैं. तो वो जूता चुराई वाली रसम होती है, बहुत महंगी पड़ी होगी आपको तो ?' इसपर हंसे हुए विक्की कौशल ने जवाब दिया, 'पाजी मैं बताता हूं, उस दिन बहुत कमाल हो गया था. 'कपिल शर्मा ने पूछा, 'वो सभी अंग्रेज हैं लेकिन उन्हें पता था ये जूता चुराई वाली रसम ?' इसपर विक्की ने कहा, 'हां-हां, उनको पता

लगा तो उन्होंने कहा बाकी शादी का तो पता नहीं लेकिन ये वाली रसम तो उन्हें करनी है. लुधियाना से मेरे दो भाई आए थे और उन्होंने कहा टेंशन ना लो हम संभाल लेंगे सबकुछ. तो जैसे ही मंडप पर जा रहे थे, बहनें आ गई और खींचना शुरू, दोनों भाई भी झगड़ने लगे, मैंने कहा दफा हो जाओ, जो लेना है ले लो और जाओ. 'विक्की ने आगे कहा, 'लेकर वो लोग चले गए और कहीं जाकर छुपा दिया. दोपहर के फेरे थे, फेरे जब खत्म हुए तो कैटरीना को सनसेट में कुछ फोटोशूट करवाना था. फेरे हो गए, सबसे मिल लिए और अब फोटो करना है. मैंने कहा कराओ, जूता है नहीं दूल्हे के पास, सन जा रहा है, और कैटरीना ने डांट लगाई उनको जूता कहाँ है इसका. मैंने कहा हमको कहाँ पता, आपको पता, जूता तो आपको बहनों के पास है. फिर कैटरीना ने ही उनकी परेड लगाई, जूता लेकर आओ इसका अभी के अभी. बहनें बोल रहीं ला रहे लेकिन पैसे, तो वो कहती हैं पैसे मुझे नहीं पता जूते लाओ सनसेट के पहले फोटो नहीं आई तो मैं देख लूंगी तुम सबको. फिर सब दौड़कर गई, फ्री में आए जूते. '



टीवी एक्ट्रेस की इस फिल्म ने भारत में
की सबसे ज्यादा कमाई, 52 की उम्र में
हैं कुंवारी, एक बच्चे की हैं मां



बॉलीवुड में हर साल ढेरों फिल्में आती हैं. कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा देती हैं तो कुछ फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं. अक्सर ही कुछ ऐसी कहानियां भी आती हैं जो फैस का दिल छू लेती हैं. ऐसी ही एक फिल्म साल 2016 में भी आई थी जो न केवल बॉलीवुड बल्कि भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी थी. आज भी वो फिल्म नंबर 1 बनी हुई है.

खास बात ये है कि इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले एक्टर की पत्नी का किरदार एक टीवी एक्ट्रेस ने निभाया था. अगर इतना कुछ बताने के बाद भी आप नहीं समझ पाए हैं कि वो फिल्म कौन सी थी तो हम आपको बता देते हैं. हम फिल्म 'दंगल' की बात कर रहे हैं. 'दंगल' में लीड रोल आमिर खान ने निभाया था. वो पहलवान महावीर सिंह फोगाट के किरदार में थे. जबकि उनकी पत्नी दया शोभा कौर का किरदार साक्षी तंवर ने निभाया था.

52 साल की उम्र में भी कुंवारी हैं साक्षी

साक्षी तंवर टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है. साक्षी का जन्म 12 जनवरी 1973 को राजस्थान के अलवर में हुआ था. उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2001 में आए सीरियल 'करम' से की थी. लेकिन उन्हें 'कहानी घर घर की' और 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे पॉपुलर टीवी शोज से पहचान मिली थी. इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया का रुख भी किया. अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काफी कुछ हासिल कर चुकीं साक्षी पर्सनल लाइफ में अकेली रह गईं. 52 साल की उम्र पार करने के बावजूद उन्होंने शादी नहीं की.

बिन ब्याही मां बन चुकी हैं साक्षी

साक्षी तंवर ने चाहे शादी नहीं की हो लेकिन फिर भी वो मां बन चुकी हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने अपने अकेलेपन को भरने के लिए बेटी दिलवा तंवर को साल 2018 में गोद लिया था. उस समय दिलवा करीब नौ महीने की थी. अब एक्ट्रेस की बेटी करीब सात साल की हो चुकी हैं. साक्षी 45 साल की उम्र में बिन ब्याही मां बनी थीं.

दंगल ने कमाए थे 2000 करोड़ से ज्यादा

'दंगल' ने न सिर्फ भारत में धूम मचाई थी, बल्कि दुनियाभर में इस फिल्म ने सुर्खियां बटोरी थी. नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बनी 'दंगल' का हिस्सा फातिमा सना शेख, सुहानी भटनागर, जायरा वसीम और सान्या मल्होत्रा भी थीं. 2074 करोड़ रुपये के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ दंगल भारत की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है.

**92 अवॉर्ड जीते, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया,
फिर भी शाहरुख-अमिताभ की
फिल्म से पीछे रह गए ऋतिक**



सुपरस्टार ऋतिक रोशन ने अपने फिल्मी करियर का आगाज साल 2000 में किया था. ऋतिक रोशन ने अपने पिता राकेश रोशन के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'कहो ना प्यार है' से बॉलीवुड में कदम रखा था और ऋतिक पहली ही फिल्म से दर्शकों का दिल जीतने में कामयाब हो गए थे. इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. ऋतिक रोशन ने पहली फिल्म के जरिए ऐसा जादू चलाया जिसकी आज भी खूब चर्चा होती है. 'कहो ना प्यार है' काफी सफल हुई थी. इस फिल्म ने 92 अवॉर्ड जीते थे और इसके लिए इसे 'गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स' में जगह मिली थी. लेकिन इस फिल्म को कमाई के मामले में उसी साल रिलीज हुई अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की फिल्म 'मोहब्बतें' ने पटखनी दी थी. 92 अवॉर्ड जीतने के बावजूद ऋतिक की फिल्म अमिताभ बच्चन की पिछर से कलेक्शन के मामले में मात खा गई थी.

'कहो ना प्यार है' ने कमाए थे 80 करोड़

'कहो ना प्यार है' 14 जनवरी 2000 को रिलीज हुई थी. इसने इस साल जनवरी में अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं. इसमें ऋतिक के अपोजिट अहम रोल में अमीषा पटेल नजर आई थीं. ये ऋतिक के साथ ही अमीषा की भी डेब्यू फिल्म थी. दोनों कलाकारों ने बॉलीवुड में हिट डेब्यू किया था. फिल्म की कहानी के साथ ही इसके गानों ने भी फैस को दीवाना बना लिया था. 10 करोड़ में बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कहर बरपा दिया था. कहो ना प्यार है का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करीब 80 करोड़ रुपये हुआ था. ये उस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनी थी.

'मोहब्बतें' हुई ब्लॉकबस्टर

साल 2000 में ही 'मोहब्बतें' भी रिलीज हुई थी. इसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान के अलावा ऐश्वर्या राय ने भी लीड रोल प्ले किया था.

इन तीनों दिग्गजों के अलावा फिल्म में जिमी शेरगिल, प्रीती झिंगियानी, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज और किम शर्मा जैसे सितारों ने भी काम किया था. मोहब्बतें का डायरेक्शन आदित्य चोपड़ा ने किया था. फिल्म 13 से 19 करोड़ रुपये के बजट में तैयार हुई थी. वहीं इसने दुनियाभर में 90 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी और ये मल्टीस्टार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही. मोहब्बतें साल 2000 की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी बनी.

मेंटर में चलाया व्यापक तलाशी अभियान

पुंछ
मेंटर उपजिला के भाटाधुडिया इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया। नियमित निगरानी के दौरान संदिग्ध गतिविधि का पता चलने के बाद तत्काल कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अभियान अभी भी जारी है। एसएसपी पुंछ शफकत भट के निर्देश पर आज अभियान शुरू हुआ। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस और विशेष अभियान समूह (एसओजी) की संयुक्त टीम को तुरंत सक्रिय किया गया। अभियान का नेतृत्व एसएसपी मेंटर मोहन शर्मा और एसपी एसओजी सुरनकोट सचिन गुप्ता कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षाबल इलाके की घेराबंदी करके किसी भी संदिग्ध तत्व को पकड़ने के लिए गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं।

बिजली बोर्ड में बड़े पैमाने पर होगी फ़ील्ड स्टाफ की भर्ती: सुक्खू

शिमला
मुख्यमंत्री सुखचंद्र सिंह सुक्खू ने सोमवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतर और निबांध बिजली सुविधा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने बैठक में ऐलान किया कि बिजली बोर्ड के कार्यों को बेहतर और सुचारु रूप से संचालित करने के लिए बोर्ड में फ़ील्ड स्टाफ की बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने कहा कि एचपीपीटीसीएल के अधिकारी और कर्मचारी राज्य में निबांध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिनके प्रयासों को उन्होंने सराहना भी की। सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में विद्युत बोर्ड के कई अधिकारी ऊर्जा निदेशालय, एचपीपीसीएल और पावर कॉर्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि इन अधिकारियों को 30 अप्रैल तक उनके संबंधित विभागों में स्थायी रूप से समायोजित होने का विकल्प दिया जाए। पद रिक्त होंगे, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा, ताकि बोर्ड की कार्यप्रणाली बेहतर हो सके। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 100 मेगावाट की क्षमता वाली उहल चरण-3 जल विद्युत परियोजना का जल्द उद्घाटन किया जाएगा।

वक्फ कानून: विपक्षी दलों ने उमर पर रिजिजू के लिए लाल कालीन बिछाने पर निशाना साधा



श्रीनगर
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को यहां एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में केंद्रीय मंत्री किशन रिजिजू से मुलाकात की, इस मुलाकात की विपक्षी दलों ने आलोचना की और इसे वक्फ कानून के प्रति सौहार्द करार दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला भी इस मुलाकात के दौरान मौजूद थे। विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने इस मुलाकात को लेकर सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि वक्फ अधिनियम पारित करने के मामले में वह बिना किसी दिखावे के भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। पीडीपी नेता नईम अख्तर ने कहा कि वक्फ कानून में सौहार्द इतनी जल्दी। जब सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य इस मुद्दे पर विधानसभा में नाटक कर रहे थे तब दिखावा भी नहीं किया गया। रिजिजू ने

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में संसद में विधेयक का संचालन किया। पीडीपी के एक अन्य नेता और पुलवामा से पार्टी के विधायक वहीद पारा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के मुसलमानों को सरकार के राजनीतिक रंगमंच में एक सहारा मात्र बना दिया गया है मंच पर तो वे उपयोगी हैं लेकिन जब वास्तविक निर्णय लिए जाने हों तो उनका प्रतिनिधित्व करना बहुत असुविधाजनक है। पारा ने एक्स पर आरोप लगाया कि इस बीच, तमिलनाडु ने वक्फ विधेयक को पूरी तरह से खारिज कर दिया है क्योंकि उनके पास विरोध करने की हिम्मत है। लेकिन एनसी हमारे लोगों और संस्थानों की कीमत पर राजनीतिक लाभ के लिए आत्मसमर्पण करती रहती है। पुलवामा के विधायक ने कहा कि एनसी ने केंद्रीय मंत्री के लिए ट्यूलिप गार्डन में लाल कालीन बिछाया है जिन्होंने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया।

दलित, आदिवासी, पिछड़ा की लड़ाई हम लड़ेंगे: राहुल बिहार में राहुल गांधी ने किया संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित



बुलाओ मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपको लड़ाई मेरी लड़ाई है। इससे पहले राहुल गांधी "पलायन रोको नीकरी दो यात्रा" में शामिल होने के लिए बेगूसराय के सुभाष चौक पर पहुंचे। यहां से राहुल गांधी पैदल ही सुभाष चौक से लेकर हर हर महादेव चौक तक यात्रा में शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत में जुटे हुए थे। जगह-जगह राहुल गांधी को फूल बरसा कर उनका स्वागत किया। यह पदयात्रा कन्हैया कुमार के नेतृत्व में की गई थी। राहुल गांधी को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। उल्लेखनीय है कि नमक सत्याग्रह आंदोलन की 95वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें नोनिया समाज के अमर शहीद बुद्ध

बेगूसराय में राहुल की पद यात्रा महज 24 मिनट में हुई समाप्त

पटना/बेगूसराय
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बेगूसराय में पदयात्रा महज 24 मिनट में खत्म हो गई। वह कन्हैया कुमार की 'पलायन रोको और नीकरी दो' यात्रा में शामिल होने आए थे। इसके बाद राहुल गांधी पटना के लिए रवाना हो गए। राहुल गांधी का बेगूसराय में 11 बजे से लेकर 11:45 बजे तक कार्यक्रम तय था। इस दौरान

उन्हें पदयात्रा में शामिल होने के साथ ही नुककड़ सभा को भी संबोधित करना था, लेकिन राहुल तय समय से 4 मिनट पहले ही 11.41 बजे ही पटना के लिए रवाना हो गए। कपस्या चौक टाउनशिप गेट के पास होने वाली नुककड़ सभा क्यों रद्द की गई, अभी तक इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है। राहुल की पदयात्रा के दौरान करीब 10 हजार लोग मौजूद थे।

नोनिया के योगदान के साथ ही शहीद प्रजापति रामचंद्र विद्यार्थी का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान पर

स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट घटा- खरगे

नई दिल्ली
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तरफ से विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि, देश की स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में है और केंद्र ने पिछले पांच सालों में स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट 42 फीसदी घटाया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार पर देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को बहाल करने का आरोप लगाया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक 2 मिनट 8 सेकेंड का वीडियो पोस्ट किया है। इसके साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने लिखा, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ये जानना जरूरी है कि आखिर किस तरह मोदी सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को आईसीयू में पहुंचाया है।

खरगे ने एक्स वीडियो पोस्ट कर कसा तंज
इस वीडियो की शुरुआत में लिखा गया है, 'दवाई, इलाज पर महंगाई की भाजपाई गोली।' इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खरगे दावा किया है कि महंगे इलाज और कम सरकारी खर्च के आंकड़े सरकार के काम की गवाही दे रहे हैं।

वीडियो में क्या-क्या दावे किए गए?



कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से पोस्ट किए गए वीडियो में दावा किया गया है कि, 5 साल से देश की चिकित्सा मुद्रास्फीति 14% रही, जिससे इलाज कराने का खर्च अधिक बढ़ गया। इस अप्रैल से 900 जरूरी दवाइयों के दमा बढ़े हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाले देते हुए यह भी कहा गया है कि हर साल 10 करोड़ भारतीय महंगे इलाज की वजह से गरीबी की कगार पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ ये भी कहा गया है कि, आम लोगों को स्वास्थ्य और जीवन बीमा के प्रीमियम पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। उन्होंने चिकित्सा में उपयोग होने वाली आवश्यक वस्तुओं पर लगे जीएसटी की ओर इशारा किया, जिसमें मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, सर्जिकल आइटम,

पड़ियां, कीलचेयर और सैनिटरी नैपकिन पर 12 से 18% जीएसटी लगाया जाता है। एक साल में ही अस्पताल में होने वाले खर्च में 11.35% की बढ़त हुई है, जिनमें एंजियोप्लास्टी का खर्च दोगुना और किडनी ट्रांस्प्लांट का खर्च तीन गुना हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत स्वास्थ्य के लिए जीडीपी का 2.5% खर्च होना था, लेकिन मोदी सरकार ने केवल 1.84% ही खर्च किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का बजट पिछले पांच वर्षों में 42% कम हो गया है। उन्होंने खाली पदों की ओर इशारा करते हुए बताया कि भारत के 757 जिलों के 5,491 ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगभग 80% पद खाली पड़े हैं।

अमित शाह ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की अग्रिम चौकी का किया दौरा

जम्मू

जम्मू और कश्मीर के तीन दिवसीय दौरे पर आये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कठुआ जिले में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ की एक अग्रिम चौकी का दौरा किया। यहां पिछले एक पखवाड़े से पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोपहर के आसपास जम्मू से कठुआ के हीरानगर सेक्टर के लिए एक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। उन्हें बाद में जमीनी हालात का आकलन करने के लिए सीमा



सुरक्षा बल (बीएसएफ) चौकी हथिनयह्क ले जाया गया। बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, बीएसएफ के महानिरीक्षक, जम्मू

फ़टियर, शशांक आनंद और जम्मू क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन टूटी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गृह मंत्री की अगुवानी की। वरिष्ठ अधिकारी गृह मंत्री को सीमा पर जमीनी हालात

के बारे में जानकारी देंगे। अमित शाह कठुआ से लौटने के बाद जम्मू में राजभवन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस कर्मियों के परिवार के सदस्यों से भी मिलेंगे और अनुकंपा के आधार पर चयनित कुछ पुलिसकर्मियों के स्वजनों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। पिछले साल अक्टूबर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद शाह का केंद्र शासित प्रदेश का यह पहला दौरा है। मंगलवार को शाह श्रीनगर में राजभवन में एक बैठक में केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न विकास कार्यक्रमों का जायजा लेंगे।

मतदान के दौरान वीवीपैट पर्चियों की 100% गिनती की याचिका खारिज

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक गिनती के अलावा वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों की 100 प्रतिशत हाथों से गिनती के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ इस मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 अगस्त, 2024 के फैसले



के खिलाफ हंस राज जैन की याचिका पर विचार कर रही थी। 'विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं'। सिजीआई ने हंस राज जैन की अपील को खारिज करते हुए कहा,

'हमें (दिल्ली उच्च न्यायालय के) विवादित फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।' सिजीआई ने आगे कहा कि उनके नेतृत्व वाली शीर्ष

अदालत की पीठ ने पहले भी इसी तरह के मुद्दे उठाते हुए एक फैसला सुनाया था और इसे बार-बार नहीं उठाया जा सकता।

महिलाओं के यौन उत्पीड़न मामले पर कर्नाटक के मंत्री के बिगड़े बोल

नई दिल्ली
कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर महिला यौन उत्पीड़न को लेकर दिए बयान पर विवादों में घिर गए हैं। बेंगलुरु में दो युवतियों से बीच सड़क पर हुई छेड़छाड़ की घटना पर उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बड़े शहरों में अक्सर होती रहती हैं। जो भी कानूनी कार्रवाई की जानी है, वह कानून के अनुसार की जाएगी। मंत्री के इस बयान को लेकर भाजपा हमलावर हो गयी है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने

पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोमवार को कहा कि कर्नाटक के गृहमंत्री ने एक ऐसी घटना को महत्वहीन बताया है जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया है, खासकर कर्नाटक के लोगों और खास तौर पर महिलाओं को। कर्नाटक में एक व्यक्ति ने एक महिला का यौन उत्पीड़न किया। सीसीटीवी फुटेज में घटना कैद हो गई। तीन से चार दिन हो गए हैं, फिर भी कर्नाटक पुलिस अपराधी को पकड़ने में असमर्थ है।

उत्तर भारत में गर्मी का कहर, 21 शहरों में पारा 42 डिग्री से ऊपर

नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी समेत उत्तर से लेकर मध्य और पूर्वी भारत में गर्मी का कहर शुरू हो गया है। पांच राज्यों के 21 शहरों में रविवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया। राजस्थान के बाड़मेर में पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तापमान 38.2 डिग्री रहा, लेकिन मौसम विभाग ने बुधवार तक लू चलने की चेतावनी दी है और यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और यहां तक कि ओडिशा के शहरों में भी लोगों को झुलसा देने वाली गर्मी का सामना करना



पड़ेगा। अप्रैल के पहले सप्ताह में लगभग हर शहर में 3 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि देखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की गति में कमी ने गर्मी के

बढ़ने में अहम भूमिका निभाई है, खासकर दिल्ली में। विभाग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सुबह के समय हवा की गति 8-10 किमी प्रति घंटे रहती है, दोपहर

तक यह कम होकर 4-6 किमी प्रति घंटे तक आ जाती है और फिर शाम तक गति कुछ बढ़ती तो है, लेकिन 8 किमी प्रति घंटे से कम ही रहती है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों तक दिल्ली के अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, उत्तर भारत और मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों में लू जैसी स्थिति की चेतावनी दी है। इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत, महाराष्ट्र और दक्षिणी भारत में अगले चार दिनों में पारा 2 से 4 डिग्री तक बढ़ेगा और उसके बाद के तीन दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट

आ सकती है। पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बीते 24 घंटे में तापमान 40 से 43 डिग्री के बीच रहा।

यूपी में बढ़ेगा रात का पारा
मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में रात के तापमान में भी बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। रविवार को प्रदेश के लगभग 10 जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग ने सोमवार व मंगलवार को आगरा और दिल्ली से सटे जिलों गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के इलाकों में लू के थपड़े चलने की चेतावनी जारी की है।

चार धाम यात्रा मार्गों पर यात्रियों को बेहतर उपलब्ध कराई जाएगी स्वास्थ्य सुविधाएं

देहरादून
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा

कि चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिये

विभागीय अधिकारियों को यात्राकाल का ठोस रोडमैप बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यात्रा मार्गों पर तैनात

आपतकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 के रिसांस टाइम को घटाकर 15 मिनट करने के निर्देश दिए गए हैं।

सोमवार को शासकीय आवास पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने

विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चार धाम यात्रा को लेकर समीक्षा बैठक की।